प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की पहचान के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति (ईओआई)
हेतु आमंत्रण

अनिल स्पेशल स्टील इंडस्ट्रीज लि. (एएसएसआईएल)

सीपी. (आईबी)-35(एनडी)/2018 में माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, दिल्ली दिनांक 5-3-2018 के आदेशानुसार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी 2016) के अध्याय II के अधीन निगमित दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के अनुपालन में

एएसएसआईएल के पास जयपुर के चौमू जिले स्थित अपनी इकाई में टीएमटी रीबारों के निर्माण की सुविधाएं हैं, जो लगभग 5 एकड़ से भी अधिक जमीन पर फैला हुआ है साथ में इंडक्शन फर्नेस (12 एमटी x 2), कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीनरी, संबंधित उपकरण तथा अवसंरचना है। नीचे उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की पहचान के लिए वित्तीय रूप से मजबूत तथा अपेक्षित निवेशकों से ईओआई आमंत्रित की जाती है :

1. वित्तीय मानदंड :

समान अथवा समरूप व्यवसाय के अनुभव के साथ दिनांक 31-3-2017 को न्यूनतम निवल सम्पत्ति रु. 50 करोड़ तथा न्यूनतम कारोबार रु."100 करोड़ होना चाहिए

अथवा

दिनांक 31.03.2017 को न्यूनतम निवल सम्पत्ति रु. 150 करोड़ होनी चाहिए

2. आईबीसी, 2016 की धारा 29ए के अधीन एक प्रस्ताव आवेदक बनने के अयोग्य नहीं होना चाहिए

ईओआई के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :

1. केवाईसी दस्तावेज (पहचान के साक्ष्य, पता का साक्ष्य, पैन)
2. दिनांक 31-3-2017 की निवल सम्पत्ति अभ्यासरत सीए/सीएस द्वारा अभिप्रमाणित होनी चाहिए
3. पिछले 3 वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
4. आवेदक के आईबीसी, 2016 की धारा 29ए के अधीन एक प्रस्ताव आवेदक के रूप में योग्य होने संबंधी हलफनामा
5. आईबीसी, 2016 की धारा 29(2) के अधीन गोपनीयता शपथ पत्र
6. "अनिल स्पेशल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड" के नाम प्रसंस्करण शुल्क के रूप में दिल्ली में भुगतेय रु. 1,00,000/- का डिमांड ड्राफ्ट
7. इच्छा की अभिव्यक्ति जमा को अधिकृत करने वाला बोर्ड का प्रस्ताव/प्राधिकार पत्र/पावर ऑफ अटर्नी

ईओआई जमा करने की अंतिम तारीख **18 जून, 2018** है।

ऊपर उल्लिखित दस्तावेज के साथ ईओआई ईमेल आईडी-**bajgj.vikram@gmail.com** पर भेजी जानी चाहिए तथा उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट द्वारा नीचे उल्लिखित पते पर भेजी जानी चाहिए : **विक्रम बजाज, प्रस्ताव पेशेवर, अनिल स्पेशल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
313ए, वर्धमान नॉर्थेक्स प्लाजा, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

किसी भी तरह के अनुसंधान के लिए आवेदक **सुश्री शिखा चौधुरी** को **9811527752** पर कॉल कर सकते हैं।

एएसएसआईएल के प्रस्ताव पेशेवर (आरपी) / ऋणदाताओं की कमिटी (सीओसी) अपने एकल इच्छा के अनुसार ईओआई के मूल्यांकन के आवश्यक समझे जाने वाले ऐसी अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज की मांग कर सकते हैं। एएसएसआईएल के आरपी/सीओसी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी ईओआई को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदक द्वारा ईओआई जमा किए जाने से ही उसके पक्ष में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा तथा इस विषय पर सीओसी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। आईबीसी, 2016 के अधीन सीआईआरपी के अनुसार प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की पहचान के लिए यह ईओआई के लिए एक आमंत्रण है तथा तत्पश्चात भागीदारी सीओसी/आरपी द्वारा चयन पर आधारित होगा। यह कोई प्रस्ताव दस्तावेज का गठन नहीं करता है।

विक्रम बजाज
IBBI/IPA-002/IP-N00003/2016-17/10003
प्रस्ताव पेशेवर, अनिल स्पेशल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड
12, वसुधा अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 41, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली-110085

'एमेजॉन का भला दिन'

करण चौधरी
नई दिल्ली, 6 जून

ऑनलाइन मार्केटप्लेस एमेजॉन भले ही भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शॉपिंग साइट है, लेकिन इसके संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस का मानना है कि अभी भी यहां कंपनी का पहला दिन है। अमेरिका के बाहर एमेजॉन के लिए भारत दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण बाजार है। एमेजॉन इंडिया स्थानीय भारतीय भाषाओं पर काम कर ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करने की कवायद में लगी है। एलेक्सा के माध्यम से धार्मिक गीतों की स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुति से लेकर स्थानीयकरण के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटप्लेस देश की संस्कृति का हिस्सा बन गई है और उसी के मुताबिक अपनी सभी सेवाएं व पेशकश दे रही है।

बेजोस ने साफ किया कि एमेजॉन इंडिया अभी नहीं बल्कि पिछले दो साल से भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट बनी हुई है। एमेजॉन ने भारत में 5 साल पूरे कर लिए हैं। वह स्थानीय लोगों में लोकप्रिय स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के मुकाबले आगे बढ़ने में सफल रही है। उपभोक्ताओं को लिखे पत्र में बेजोस ने कहा है कि एमेजॉन की पहुंच अब देश में सेवा योग्य 100 प्रतिशत पिनकोड तक है और 13 राज्यों में स्थित 50 से ज्यादा गोदामों से सामान पहुंचा रही है।

पत्र में उन्होंने कहा है, 'हमने अपनी यात्रा के 5 साल पूरे किए हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि एमेजॉन का यह पहला दिन है। मैं आगे की संभावनाओं को लेकर उत्साहित हूं। एमेजॉन डॉट इन इंडिया की की अपनी दुकान है।'

एमेजॉन इंडि

2014 में
2 अरब डॉलर
निवेश की
प्रतिबद्धता
जताई

निवेश बढ़ सकता है क्योंकि वालमॉर्ट
त में फ्लिपकार्ट के परिचालन का विस्तार
ना चाहती है। एमेजॉन की अन्य भारतीय
इयों में निवेश किया गया है, जिसमें
जॉन पे और वहां स्थित इसका थोक
बार शामिल है।

सूत्रों के मुताबिक वैश्विक ई कॉमर्स
ज ने भारत से सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट
खुदरा कंपनियों से हिस्सेदारी खरीदने
लिए बातचीत शुरू की है। कंपनी की
ना भारत में अपनी ऑफलाइन पहुंच
ने की है।

इस दिशा में बातचीत अभी शुरुआती दौर
, लेकिन सूत्रों ने कहा कि बड़े खुदरा
बारियों ने एमेजॉन के साथ बातचीत की
हाल ही में फ्लिपकार्ट वालमार्ट सौदे की
णा के बाद फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक
ोर बियाणी ने संकेत दिए थे कि वह
द वैश्विक खुदरा कारोबारी को
सेदारी बेचने को तैयार हैं।

सूत्रों ने कहा कि बियाणी ने एमेजॉन और
मॉर्ट के साथ बातचीत की है। कुछ
य हाइपरमार्केट और सुपरमार्केट चलाने
ों के साथ भी एमेजॉन ने बातचीत की
सूत्रों ने कहा कि यह वालमॉर्ट द्वारा
पकार्ट में 16 अरब डॉलर निवेश की
क्रिया नहीं है बल्कि कंपनी पहले से ही
फलाइन कारोबार की योजना बना रही
एक सूत्र ने कहा, 'अमेरिका की ही
वह भारत में खुदरा क्षेत्र में विस्तार
ती है। एमेजॉन ने कुछ कंपनियों के
बाद की है, लेकिन अभी यह
आती अवस्था में है। अगर चीजें सही
में जाती हैं तो इस साल के आखिर
एक बड़े खुदरा कारोबारी के साथ
हो सकता है।' बहरहाल एमेजॉन

काम कर रही है, जिस
असिस्टेंट की क्षमता ब

पिछले 5 साल के दौ
विक्रेता के साथ काम
3,00,000 विक्रेता जोड़
पिछले एक साल में ही
अपने थर्ड पार्टी नेटवर्क
का विस्तार किया है, जिस
हो सके कि छोटे शहरों औ
आसानी से पहुंच सकें

कर्मचारियों की छुट्टी कर खस्ताहाल उपक्रमों की जमीन पर बनेंगे मकान

भाषा
नई दिल्ली, 6 जून

सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को आज मंजूरी दी। नए नियमों के अनुसार ऐसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते मकानों की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार की इस पहल से घाटे में चल रहे इन उपक्रमों को बंद करने की योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी को कम किया जा सकेगा। नए दिशानिर्देशों में परिसमापन प्रक्रिया में दिए गए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की भूमि को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराने को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। नए नियमों के मुताबिक ऐसे उपक्रमों के हर स्तर के कर्मचारी को सरकार द्वारा तय समान नीति के तहत 2007 के राष्ट्रीय वेतन मानकों के अनुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) पैकेज दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इन